GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT
DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.182
TO BE ANSWERED ON 03.08.2022

SELF HELP GROUPS

182 DR. ASHOK KUMAR MITTAL:

Will the Minister of RURAL DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the salient features of the Self Help Groups (SHGs) scheme and the current status of its implementation in the country;
(b) the funds allocated and utilized under the scheme during the last year and the current year, State-wise/UT-wise, including Punjab;
(c) the number of people, including women and persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who have benefitted under the scheme in the State of Punjab; and
(d) the States that have rolled out the transaction based monitoring system for the evaluation of works done by SHGs, the details thereof?

ANSWER
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
(SHRI GIRIRAJ SINGH)

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT (a) to (d) REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. *182 TO BE ANSWERED ON 03.08.2022.

(a) The Government is implementing Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY – NRLM) across the country in a mission mode with the objective of organizing the rural poor women into Self Help Groups (SHGs) and continuously supporting them to access credit at affordable rates from banks and take up various livelihoods activities for increasing their household income. The programme is being implemented in all the States (including Punjab) and Union Territories, except Delhi and Chandigarh. Under DAY - NRLM, Revolving Funds (RF) and Community Investment Fund (CIF) are provided to Self Help Groups (SHGs) and their federations to create financial resources from which loans are provided to their members for their needs including livelihoods activities.
As of 28th July 2022, the Mission is being implemented in 6842 blocks in 721 districts across all 28 States and 6 UTs. Cumulatively, 8.41 crore women have been mobilized into more than 77.40 lakh SHGs. Further, the SHGs have been federated into 4.37 lakh village level federations and more than 28589 cluster level federations. A total of Rs.19249 crore of capitalisation support (Revolving Funds and Community Investment Funds) has been provided to SHGs and their federations. From FY 2013-14, an amount of Rs. 5.24 lakh crore bank credit has been accessed by women SHGs under DAY-NRLM.

(b) The funds allocated and utilized under the scheme during the current year and the last year, State/UT-wise, including Punjab is placed at Annexure.

(c) As of 30th June 2022, the Mission has covered 3,41,656 rural women in the State of Punjab, out of which 2,32,665 women members are from Scheduled Castes.

(d) A transaction based monitoring system was implemented from the year 2018 in the following States/UTs for monitoring of the work done by the SHGs:-

Arunachal	Jammu & Kashmir	Meghalaya	Tamil Nadu	Andhra Pradesh
Assam	Karnataka	Mizoram	Telangana	Jharkhand
Chhattisgarh	Kerala	Nagaland	Tripura	Rajasthan
Gujarat	Madhya Pradesh	Odisha	Uttarakhand	
Haryana	Maharashtra	Punjab	Uttar Pradesh	
Himachal Pradesh	Manipur	Sikkim	Pudducherry	

Further, the Ministry has now developed an improved application for capturing the transactions in the SHGs, Village Organisations and Cluster level Federations with Android based technology to monitor the performance and activity being carried out by SHGs. The system has been piloted successfully in four States i.e Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana and Meghalaya and training has been provided to nearly 6000 officials and Community members across the country to implement the monitoring system at ground level.

******

Annexure referred in reply to Part (b) of Rajya Sabha *Starred Question No. 182 for answer on 03.08.2022 regarding "Self Help Groups "

(Amount in Rs lakh)

S.No	State/UT	2021-22		2022-23 (as on 31st July, 2022)	
		Central Allocation	Central Release	Central Allocation	Central Release
		NRLM/NRETP	NRLM/NRETP	NRLM/NRETP	NRLM/NRETP
1	Andhra Pradesh	25166.83	12583.42	25172.97	0.00
2	Bihar*	112173.22	112173.22	112300.29	0.00
3	Chhattisgarh*	28153.98	25474.48	28628.47	0.00
4	Goa	700.00	350.00	750.00	0.00
5	Gujarat*	17439.87	12668.42	18233.44	0.00
6	Haryana	9554.21	2388.55	9556.55	0.00
7	Himachal Pradesh	4023.63	4023.63	4024.62	402.87
8	Jammu & Kashmir	14668.93	11001.70	18016.86	0.00
9	Jharkhand*	45582.58	42140.68	43395.23	0.00
10	Karnataka*	33664.98	25520.19	36307.14	0.00
11	Kerala	14618.18	7309.10	14621.75	0.00
12	Madhya Pradesh*	54834.35	25917.18	56166.28	0.00
13	Maharashtra*	56398.72	28199.36	71020.83	0.00
14	Odisha*	55346.87	66183.59	53193.67	7398.90
15	Punjab	4643.24	2321.62	4644.38	477.68
16	Rajasthan*	28179.35	25598.68	28469.30	0.00
17	Tamil Nadu*	39948.01	39498.01	40065.62	0.00
18	Telangana	17976.30	4494.08	17980.69	0.00
19	Uttar Pradesh*	153757.57	149066.36	152774.55	0.00
20	Uttarakhand	7779.53	7620.73	7781.43	0.00
21	West Bengal*	64439.23	48329.43	62262.18	0.00
22	A&N Islands	600.00	450.00	900.00	0.00
23	Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli	400.00	100.00	600.25	0.00
24	Lakshadweep	200.00	100.00	238.95	59.72
25	Ladakh	1320.00	330.00	1319.20	0.00
26	Puducherry	1000.00	500.00	1700.00	0.00
27	Arunachal Pradesh	8289.42	4144.71	13225.95	0.00
28	Assam*	36998.66	36323.66	43091.95	0.00
29	Manipur	10273.53	2568.38	12538.30	0.00
30	Meghalaya	14375.43	7187.72	16928.17	0.00
31	Mizoram	10540.55	2635.14	15671.94	0.00
32	Nagaland	17118.28	4279.57	17793.90	0.00
33	Sikkim	4431.85	1079.84	6648.53	1662.13
34	Tripura	17364.21	8682.11	24162.21	0.00
	Total	**911961.51**	**721243.56**	**960185.60**	**10001.30**

*NRETP is being implemented in these States

NRETP: National Rural Economic Transformation Project

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 182*
(03 अगस्त, 2022 को उत्तर दिए जाने के लिए)

स्वयं सहायता समूह

***182. डॉ. अशोक कुमार मित्तल:**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और देश में इसके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस योजना के अधीन पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी राशि आबंटित की गई और कितनी राशि का उपयोग किया गया;

(ग) पंजाब राज्य में इस योजना के अधीन महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों सहित कितने लोग लाभान्वित हुए; और

(घ) किन राज्यों ने स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन के लिए संव्यवहार आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

****

राज्य सभा में दिनांक 03.08.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *182 के उत्तर के भाग (क) से (घ) में उल्लिखित विवरण

(क): सरकार देश भर में दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) का मिशन मोड़ में कार्यान्वयन कर रही है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और बैंकों से सस्ती दरों पर ऋण प्राप्त करने और अपनी घरेलू आय बढ़ाने के लिए विभिन्न आजीविका गतिविधियों को शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करना है। सभी राज्यों

(पंजाब सहित) और दिल्ली तथा चंडीगढ़ को छोड़कर अन्य सभी संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। डीएवाई-एनआरएलएम कार्यक्रम के अंतर्गत, स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और उनके संघों को परिक्रमी निधि (आरएफ) और समुदाय निवेश निधि (सीआईएफ), उनके वित्तीय संसाधन निर्माण हेतु उपलब्ध कराई जाती है जिससे उनके सदस्यों को आजीविका गतिविधियों समेत अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान किया जा सके।

28 जुलाई, 2022 की स्थिति के अनुसार, मिशन का सभी 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 721 जिलों के 6842 ब्लॉकों में कार्यान्वयन किया जा रहा है। संचयी रूप से, 8.41 करोड़ महिलाओं को 77.40 लाख से भी अधिक एसएचजी में संगठित किया गया है। इसके अतिरिक्त, एसएचजी को 4.37 लाख ग्राम स्तरीय संघों और 28589 से भी अधिक क्लस्टर स्तरीय संघों में संगठित किया गया है। एसएचजी सदस्यों को ऋण देने के लिए एसएचजी और उनके संघों को कुल 19249 करोड़ रुपए की पूँजीकृत सहायता (परिक्रमी निधियाँ तथा समुदाय निवेश निधियाँ) दी गई है। वित्तीय वर्ष 2013-14 से डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत स्व सहायता समूहों ने 5.24 लाख करोड़ रूपए का बैंक ऋण प्राप्त किया है।

(ख): वर्तमान वर्ष और विगत वर्ष के दौरान योजना के तहत आवंटित एवं उपयोग की गई निधियों का पंजाब सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ग): 30 जून 2022 तक, मिशन ने पंजाब राज्य में 3,41,656 महिला सदस्यों को कवर किया है जिसमें से 2,32,665 महिला सदस्य अनुसूचित जाति से हैं।

(घ): एसएचजी द्वारा किए गए कार्यों की निगरानी के लिए निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वर्ष 2018 से एक ट्रांजेक्शन आधारित निगरानी प्रणाली लागू की गई थी:-

अरूणाचल	जम्मू और कश्मीर	मेघालय	तमिलनाडु	आंध्र प्रदेश
असम	कर्नाटक	मिजोरम	तेलंगाना	झारखण्ड
छत्तीसगढ़	केरल	नागालैंड	त्रिपुरा	राजस्थान
गुजरात	मध्य प्रदेश	ओड़िशा	उत्तराखंड	
हरियाणा	महाराष्ट्र	पंजाब	उत्तर प्रदेश	
हिमाचल प्रदेश	मणिपुर	सिक्किम	पुदुचेरी	

इसके अलावा, मंत्रालय ने अब एसएचजी द्वारा किए जा रहे कार्य निष्पादन और कार्यकलाप की निगरानी के लिए एंड्रॉइड आधारित प्रौद्योगिकी के साथ ट्रांजेक्शन आधारित उन्नत निगरानी प्रणाली तैयार की है। इस प्रणाली को चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और मेघालय में सफलतापूर्वक संचालित किया गया है और देश भर में लगभग 6000 अधिकारियों और समुदाय के सदस्यों को जमीनी स्तर पर निगरानी प्रणाली को लागू करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

*****

"स्व-सहायता समूहों" के संबंध में राज्य सभा में दिनांक 03.08.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *182 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित **अनुबंध**

(धनराशि लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2021-22		2022-23 (31 जुलाई, 2022 तक)	
		केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज
		एनआरएलएम / एनआरईटीपी	एनआरएलएम / एनआरईटीपी	एनआरएलएम / एनआरईटीपी	एनआरएलएम / एनआरईटीपी
1	आंध्र प्रदेश	25166.83	12583.42	25172.97	0.00
2	बिहार*	112173.22	112173.22	112300.29	0.00
3	छत्तीसगढ़*	28153.98	25474.48	28628.47	0.00
4	गोवा	700.00	350.00	750.00	0.00
5	गुजरात*	17439.87	12668.42	18233.44	0.00
6	हरियाणा	9554.21	2388.55	9556.55	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	4023.63	4023.63	4024.62	402.87
8	जम्मू और कश्मीर	14668.93	11001.70	18016.86	0.00
9	झारखंड*	45582.58	42140.68	43395.23	0.00
10	कर्नाटक*	33664.98	25520.19	36307.14	0.00
11	केरल	14618.18	7309.10	14621.75	0.00
12	मध्य प्रदेश*	54834.35	25917.18	56166.28	0.00
13	महाराष्ट्र*	56398.72	28199.36	71020.83	0.00
14	ओड़िशा*	55346.87	66183.59	53193.67	7398.90
15	पंजाब	4643.24	2321.62	4644.38	477.68
16	राजस्थान*	28179.35	25598.68	28469.30	0.00
17	तमिलनाडु*	39948.01	39498.01	40065.62	0.00
18	तेलंगाना	17976.30	4494.08	17980.69	0.00
19	उत्तर प्रदेश*	153757.57	149066.36	152774.55	0.00
20	उत्तराखंड	7779.53	7620.73	7781.43	0.00
21	पश्चिम बंगाल*	64439.23	48329.43	62262.18	0.00
22	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	600.00	450.00	900.00	0.00
23	दमन और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली	400.00	100.00	600.25	0.00
24	लक्षद्वीप	200.00	100.00	238.95	59.72
25	लद्दाख	1320.00	330.00	1319.20	0.00
26	पुदुचेरी	1000.00	500.00	1700.00	0.00
27	अरुणाचल प्रदेश	8289.42	4144.71	13225.95	0.00
28	असम*	36998.66	36323.66	43091.95	0.00
29	मणिपुर	10273.53	2568.38	12538.30	0.00
30	मेघालय	14375.43	7187.72	16928.17	0.00
31	मिजोरम	10540.55	2635.14	15671.94	0.00
32	नागालैंड	17118.28	4279.57	17793.90	0.00
33	सिक्किम	4431.85	1079.84	6648.53	1662.13
34	त्रिपुरा	17364.21	8682.11	24162.21	0.00

	सकल योग	**911961.51**	**721243.56**	**960185.60**	**10001.30**

*एनआरईटीपी इन राज्यों में लागू किया जा रहा है

एनआरईटीपी:राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना

श्री उपसभापति : डा. अशोक कुमार मित्तल, आप अपना पहला सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : उपसभापति महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें यह बताया गया है कि देश की 8 करोड़, 41 लाख वूमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कार्यरत हैं और देश की तरक्की में अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने कोरोना महामारी में भी अपना योगदान दिया है। किसी ने पीपीई किट बनाकर, किसी ने मास्क बनाकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। महोदय, वे जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जब उनको बेचने की बात आती है, तो उनके लिए मार्केट अवेलेबिलिटी के रिसोर्सेज़ बहुत लिमिटेड हैं। उनके लिए लोकल मार्केट रह जाती है। यदि वे एमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर जाने की कोशिश करती हैं, तो उनका 30-35 परसेंट तक पैसा कट हो जाता है, क्योंकि उन्हें कमीशन शेयर करना पड़ता है और वह प्रॉफिटेबल नहीं रहता। उपसभापति जी, मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेम्बर्स, जो कि 8 करोड़, 41 लाख हैं, जो कि हमारे हिंदुस्तान की वर्किंग वुमेन का आधा हिस्सा होगा, उनके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : डा. अशोक कुमार मित्तल, आप अपना सवाल ब्रीफ़ली पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : जी। महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, जो कि एमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट की क्वॉलिटी का मुक़ाबला कर सके, ताकि वे उस प्लैटफॉर्म पर जाकर अपना माल देश ही नहीं, बल्कि विदेश में भी बेच सकें?

ग्रामीण विकास मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छा प्रश्न खड़ा किया है। वे खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं कि यह 8 करोड़, 41 लाख की संख्या है। उन्होंने कुछ प्रॉब्लम भी रखी है, इसलिए मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि जब हम 2014-15 में सरकार में आए थे, तब हमारी 2 करोड़, 35 लाख सदस्याएं थीं और 80 हज़ार करोड़ का क्युम्युलेटिव बैंक लिंकेज था। उस वक्त एनपीए 9.58 परसेंट था। अभी 8 करोड़, 41 लाख सदस्याएं हैं और क्युम्युलेटिव बैंक लिंकेज लगभग 5 लाख, 24 हज़ार करोड़ है। अभी हम लोगों ने 'मिशन 1 लाख' लिया है, ताकि हमारी बहनें, जिनके लिए उन्होंने कहा है कि रूरल की आधी आबादी हैं, मैं उस संदर्भ में उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमने 2024 तक 10 करोड़ की संख्या तक जाने का संकल्प लिया है। हमने जो 'मिशन 1 लाख' लिया है, उसमें हमारा प्रयास है कि उनकी आमदनी 10 हज़ार रुपये से 12 हज़ार रुपये तक हो। हमने मार्केटिंग के लिए भी कई एजेंसीज़ के साथ टाई-अप किया है, उनके साथ एमओयू किया है। अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन, फ्लिपकार्ट, एमेज़ॉन या अन्य संस्थान की बात हो, राज्यों के साथ मिलकर 6 -7 राज्यों ने अपना ब्रांड भी बनाया है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में, 2024 तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मजबूत होंगे। महोदय, अगर देश में 19.5 करोड़ ग्रामीण आवास हैं, तो हम 'मिशन 1 लाख' के तहत 10 करोड़ महिलाओं को उस रास्ते पर

ले जाने का काम करेंगे, जिससे उनके द्वारा बनाए गए केवल मास्क ही नहीं, बल्कि हर सामान की मार्केटिंग के लिए हम राज्य के साथ मिलकर एक प्लैटफॉर्म तैयार करने का काम कर रहे हैं।

श्री उपसभापति : डा. अशोक कुमार मित्तल, आप अपना दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछिए। डा. साहब, आप संक्षिप्त सवाल पूछिएगा।

डा. अशोक कुमार मित्तल : जी। उपसभापति जी, शायद मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। ..(**व्यवधान**)...

श्री गिरिराज सिंह : दे दिया है। ..(**व्यवधान**)...उसमें जोड़ रहे थे। ..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप आपस में बात मत कीजिए। प्लीज़, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से उनसे यह और पूछना चाहता हूं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जैसे एमेज़ॉन है या और कोई है, उनके प्लैटफॉर्म के मुक़ाबले आप ऐसा कौन-सा प्लैटफॉर्म ला रहे हैं, ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को अपनी 30-35 परसेंट तक की इन्कम उनके साथ शेयर न करनी पड़ी?

श्री गिरिराज सिंह : यह प्रश्न हो गया है, मैंने जवाब दे दिया है।

श्री उपसभापति : डा. अशोक कुमार मित्तल, आपका यह दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न ऑलरेडी हो गया है, इसलिए अब आप बैठ जाइए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : सर, यह मेरा दूसरा सप्लीमेंटरी प्रश्न है।

श्री उपसभापति : आपने अभी अपना दूसरा सवाल पूछा है।

डा. अशोक कुमार मित्तल : सर, वह सवाल नहीं था, वह मैंने रिपीट किया था। ..(**व्यवधान**)...

श्री गिरिराज सिंह : वह सवाल था, मैंने कहा था कि ..(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : आप कृपया आपस में बात मत कीजिए।..(**व्यवधान**)...आप अपना प्रश्न पूछिए।

डा. अशोक कुमार मित्तल : मेरा दूसरा सवाल सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिंक्ड ही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन उनकी मार्केट क्योंकि सीमित होती है और हो सकता है कि उनका वह जो प्रोडक्ट है, दूसरे प्रदेश में, जो कि साथ ही है, रॉ-मैटीरियल के तौर पर काम करे तो क्या हम कोई ऐसा क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं...(**व्यवधान**)...

श्री उपसभापति : यह सुझाव है, जल्दी सवाल पूछें।

डा. अशोक कुमार मित्तल : सवाल यह है कि हम कोई क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर काम कर सकें, एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट के साथ, ताकि उनको बेनेफिट मिल सके।

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, मैंने डाक्टर साहब के पहले प्रश्न का पहले जवाब दिया था कि एमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी टाइ-अप किया है। यह पहले भी बोला और आज भी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं कि 30 परसेंट कमीशन का, जो मार्केट प्लैटफॉर्म का पूरे देश का सिस्टम है, उसी सिस्टम में हम इनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक क्लस्टर के बारे में कहा, अभी लगभग 175 ब्लॉक्स में हम इस काम को करने के लिए एक एंटरप्रिन्योर योजना को लाये हैं।

डा. अनिल सुखदेवराव बोंडे : उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह, जो महिलाओं के हैं, वे लोन का पेमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हैं। उसमें एन.पी.ए. बहुत कम रहता है, जैसे किसानों को क्रॉप लोन के लिए हम इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, वैसे ही तीन लाख रुपये तक के कर्जे के लिए ज़ीरो इंटरेस्ट के तहत महिलाओं को लोन देने के लिए क्या कोई योजना बनी है?

श्री गिरिराज सिंह : उपसभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज देश के अंदर, इसके लिए हम इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं, पांच परसेंट तक, बैंक का जो लेंडिंग रेट होता है और जो तीन लाख रुपये तक लोन लेते हैं। ये ज़ीरो परसेंट का कह रहे हैं, ज़ीरो की अभी कोई स्कीम नहीं है। लेकिन देश के अंदर उनको वहां तक पहुंचाना, तीन तरह से पैसे राज्य सरकार की ओर से, रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी फंड और फिर बैंकों से लिंक करके, लेकिन जो उन्होंने कहा कि ज़ीरो परसेंट पर, तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

डा. अमर पटनायक : सर, यह जो एन.आर.एल.एम. स्कीम है, उसमें महिला एस.एच.जीज़ को काफी लाइव्लीहुड ऑप्शंस के लिए, लाइव्लीहुड एक्टिविटीज़ के लिए लोन दिया जाता है, लेकिन आजकल यह लाइव्लीहुड ऑप्शंस के च्वाइसेज़ बढ़ गये हैं। For example, young girls want to learn about computer training. They want to set up a kiosk. लेकिन जो kind of livelihood options that are being given currently वह सब उसी में सीमित है कि सिलाई मशीन या it is candle making unit तो मेरा सवाल यह है कि what are the kinds of skill training programmes that are being imparted under the NRLM to these women SHG groups enlarging their scope for livelihood from the market?

श्री गिरिराज सिंह : उपसभापति महोदय, इसमें मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, RSETI से हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है, वह जो एंटरप्रेन्योर DDU-GKY से जुड़े हुए हैं, लेकिन RSETI

के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि RSETI से ट्रेनिंग लेने के बाद उनको मार्केट में जाने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है।

श्री नीरज डांगी : बहुत-बहुत धन्यवाद, उपसभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की बकाया प्रथम किश्त की द्वितीय केन्द्रीयांश राशि राज्य को यथाशीघ्र जारी करने पर विचार करती है? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री गिरिराज सिंह : महोदय, मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न से उसका कुछ लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर देंगे तो मैं जवाब दे दूंगा।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Q. No. 183.